अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 11-Issue 02, (April-June 2023)

सामाजिक बुराइयों के लए उठाए गएकदम एवं उनका प्रभाव

हरिवीकेश राइ

भारत दुनिया के तेज आ र्थक वकास वाले देशों में है , पर इस वकास का लाभ गरीबों को नहीं मल रहा इसका असर उसके वकास पर भी .पड़ा, जो पछले महीनों में लगातार धीमा हुआ है.सामाजिक चुनौतियां बनी हुई हैं और गरीबी बढ़ रही है .

भारत ने **90** के दशक में आ र्थक सुधार शुरू कया प्रधानमंत्री मनमोहन संह उस समय देश . सुधारों से उम्मीद थी क लोगों के आ र्थक हालात सुधरेंगे . के वत्त मंत्री थे, ले कन शक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान न देने की वजह से गरीबी , कुपोषण, भ्रष्टाचार और लैं गक वषमता जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ी हैं .अब यह देश के वकास को प्रभा वत कर रहा है .

दो दशक के आ र्थक सुधारों की वजह से देश ने तरक्की तो की है, ले कन एक तिहाई आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रही है भारत इस अव ध में ऐसा देश . .बन गया है जहां दुनिया भर के एक तिहाई गरीब रहते हैं

चीन की कामयाबी

चीन अपने यहां गरीबों की तादाद में भारी कमी करने में कामयाब रहा है , ले कन भारत वकास के फायदे आम लोगों में समान ढंग से बांट नहीं पाया है आ र्थक सुधारों के . परिणामस्वरूप चीन का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर**12,000** अरब डॉलर हो गया है , जब क समान आबादी के बावजूद भारत का जीडीपी इसका एक तिहाई ही है प्रति व्यक्ति आय के . . मामले में दोनों देशों के बीच गहरी खाई है**2001** से **2012** के बीच भारत में औसत आय **460** डॉलर से बढ़कर **1700** डॉलर हुई है जब क चीन में इसी अव ध में यह **890** से बढ़कर **6800** डॉलर हो गया है.

पछले सालों में भारत की वकास दर करीब **9** फीसदी रही है , ले कन देहाती क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था के ज्यादातर इलाकों में आय बहुत धीमी गति से बढ़ी है .क्षेत्रीय वकास वशेषज्ञ प्रोफेसर र वशंकर श्रीवास्तव कहते हैं , "हमारा वकास गरीबों का समर्थन करने वाला वकास नहीं था ले कन मुख्य बात यह है क गरीबी पर वकास की प्र क्रया का . वषमताएं बढ़ी हैं . नतीजतन क ". प्रभाव बहुत से दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम रहा है ुपोषण और गरीबी में इस कदर बढ़ गई है क सरकार को आबादी के बड़े हिस्से को खाद्य पदार्थों की गारंटी देने के लए खाद्य सुरक्षा ऑ र्डनेंस लाना पड़ा इस पर .**1.3** अरब रुपये का खर्च आएगा.

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 11-Issue 02, (April-June 2023)

वकास की रणनीति

हाल में जारी यूएन शक्षा सूचकांक के अनुसार भारत **181** देशों में **147**वें स्थान पर है . हालां क पछले सालों में ढेर सारे गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज और यूनिव र्सटी खुले हैं, ले कन राजनीतिक इच्छा के अभाव और भ्रष्टाचार की वजह से स्तरीय शक्षा को बढ़ावा नहीं मला है आईआईटी और आईआईएम को वश्व भर में जाना जाता है ले कन वे भारत .के वर्तमान वकास के लए जरूरी इंजीनियर और मैनेजर प्र श क्षत करने की हालत में नहीं हैं देश में . औद्यो गक उत्पादन बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने के लए कामगारों और मैनेजरों के .स्तरीय प्र शक्षण की योजना जरूरी है

शोध और वकास के क्षेत्र में भी भारत पर्याप्त खर्च नहीं कर रहा है वह अपने प्रतिद्वंद् वयों . भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाले वैश्विक .चीन और द क्षण कोरिया से बहुत पीछे है खर्च का सर्फ**2.1** प्रतिशत खर्च करता है जब क यूरोप का हिस्सा **24.5** प्रतिशत है . श्रीवास्तव का कहना है क वकास की प्रवृति ऐसी होनीचाहिए क वह निचले तबके के लोगों की आय बढ़ाकर गरीबी का प्रभावशाली तरीके से मुकाबला कर सके यदि वकास का" . फोकस देश के गरीब इलाकों और बेहतर आय और स्तरीय रोजगार के जरिए लोगों को गरीबी ".से बाहर निकालने वाली रणनीतियों पर हो तो वह ज्यादा प्रभावी होगा

नहीं रुकता भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार .**176** देशों की सूची में भारत **94**वें नंबर पर है भ्रष्टाचार वरोधी अंतरराष्ट्रीय संस्था की ताजा रिपोर्ट के . भारत में . अनुसार दुनिया भर में रिश्तखोरी का स्तर काफी ऊंचा है**70** फीसदी लोगों का मानना है क पछले दो साल में भ्रष्टाचार की स्थिति और बिगड़ी है पछले साल सामाजिक . कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में वशाल भ्रष्टाचार वरोधी आंदोलन हुआ, ले कन जन लोकपाल बनाने की मांग को राजनीतिक दलों का व्यापक समर्थन नहीं मला पार्टिय .ां अपने को आरटीआई कानून से भी अलग रखना चाहती हैं.

भारत की प्रमुख कारोबारी संस्था फेडरेशन ऑफ इं डयन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है क भारत का (फक्की)**2011**से **2012** के बीच भ्रष्टाचार के कारण सात अरब डॉलर का नुकसान हुआ .**2**जी टेलीकॉम , कॉमनवेल्थ गेम्स और कोयला घोटालों से हुए नुकसान को इसमें शा मल नहीं कया गया है जो हजारों करोड़ के हैं भ्रष्टाचार का . अर्थव्यवस्था के वकास पर बहुत ही बुरा असर हो रहा है और जर्मनी जैसे देशों की वदेशी .कंपनियों ने तो इस पर अब खुलेआम अपनी चंताएं जतानी शुरू कर दी हैं

गरीबी और बेरोजगारी

नए रोजगार बनाने और गरीबी को रोकने में सरकार की वफलता की वजह से देहातों से लोगों का शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है इसकी वजह से शहरों के ढांचागत .

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 11-Issue 02, (April-June 2023)

आधुनिकता के कारण परंपरागत संयुक्त परिवार टूटे हैं . संरचना पर दबाव पैदा हो रहा है और नौकरी के लए युवा लोगों ने शहरों का रुख कया है, जिनका नितांत अभाव है नतीजे . में पैदा हुई सामाजिक तनाव और कुंठा की वजह से हिंसक प्रवृति बढ़ रही है, खासकर महिलाओं के खलाफ हिंसा में तेजी आई है दिसंबर .**2012** में नई दिल्ली में एक छात्रा के गैंगरेप ने आ र्थक महाशक्ति के रूप में उभरते भारत में महिलाओं की समस्याओं को उजागर कया है.

'भारत की समस्याएं अस्थायी'

भारत में जारी आ र्थक उथल पुथल के बीच पूर्व वत्त मंत्री यशवंत सन्हा ने कहा है क देश की समस्याएं अस्थाई हैं , उनका समाधान ढूंढा जा सकता है , ले कन उसके लए मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत है) .**11.09.2013)**

"खाद्य सुरक्षा का खर्च झेल लेंगे"

च कत्सा में पछड़ा भारत

आंकड़ों में उलझी भारत की गरीबी

"भारत के सब्र की सीमा है"

हालां क बलात्कार और छेड़ छाड़ से संबं धत कानूनों में सख्ती लाई गई है और सरकार ने महिला पु लसक र्मयों की बहाली की दिशा में कदम उठाए हैं , पूरे भारत में महिलाओं के खलाफ हिंसा में कमी नहीं आई है नई दिल्ली में सेंटर फॉर वीमेंस डेवलपमेंट स्टडीज की . निदेशक प्रोफेसर इंदु अग्निहोत्री इसकी वजह समाज में महिलाओं की है सयत को मानती हैं, जो बहुत नीची है , "यह सभी कारकों में दिखती है , खास कर आ र्थक हिस्सेदारी में उन्हें . समाजिक बोझ समझा जाता है, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोग की वस्तु समझा जाता है, जो समाज में उत्पादक योगदान नहीं देता".इसकी वजह से हिंसा बढ़ रही है .

समाज की बेरुखी

भारतीय समाज महिलाओं के मुद्दों को कस तरह नजरअंदाज कर रहा है , यह इस बात से पता चलता है क सालों से चल रही बहस के बावजूद महिलाओं के लए संसद में सीटों के लए आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है कुछ राजनीतिक . दल इसका खुलकर वरोध कर रहे हैं, जब क दूसरे अवसरवादी कारणों से इस पर जोर नहीं

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 6.789 Volume 11-Issue 02, (April-June 2023)

दे रहे हैं . इतना ही नहीं कोई भी राजनीतिक पार्टी संगठन की संरचना में महिलाओं का प्रतिनि धत्व बढ़ाने की कोई गंभीर को शश नहीं कर रही है.

भारत राजनीतिक और आ र्थक नेतृत्व में भी लैं गक वषमता का सामना कर रहा है .

आधुनिक कारोबार में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी का महत्व बढ़ गया है और बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनियां महिला मैनेजरों को आक र्षत करने के प्रयास भी कर रही हैं , ले कन अभी भी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड भारतीय कंपनियों के बोर्डरूम में महिला मैनेजरों की संख्या सर्फ तीन फीसदी है अग्निहोत्री लोगों की सोच में बदलाव की मांग .करती हैं, "यदि महिलाओं की आ र्थक दशा सुधरती है तो उनकी मुश्किलें भी कम होंगी ऐसा नहीं है .

क कमाने वाली महिलाओं को तुरंत उसके अ धकार मल जाते हैं, ले कन जो महिलाएं कमाती हैं, उनके पास वकल्प होते हैं, अपने अ धकारों पर बल देने, अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को आवाज देने और उन पर अमल करने का मौका होता है".

पछले महीनों में भारत के आ र्थक वकास में तेजी से आई कमी का कारण वैश्विक आ र्थक संकट बताया जा रहा है, ले कन वकास दर को बनाए रखने में वफलता की वजह प्रतिभाओं का इस्तेमाल न करना और कुशल कारीगरों की कमी भी है भ .ारत मुख्य रूप से गांवों में रहने वाली अपनी आबादी की क्षमताओं का इस्तेमाल करने और उन्हें शक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने में नाकाम रहा है उसे समझना होगा क उसका आ र्थक स्वास्थ्य व्यापक रूप से . .उपलब्ध प्रतिभाओं के बेहतर इस्तेमाल पर ही निर्भर है